प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 12 – 19 जुलाई 2021 मूल्य पांच रूपए

जब चुनावों से पहले ही वरिष्ठ अधिकारी केन्द्र में जाने के प्रयासों में लग जायें तो...

शिमला/शैल। प्रदेश से डीजीपी सहित तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने केन्द्र मे जाने के लिये आवेदन कर दिया है। डीजीपी संजय कुंडु तो मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं इस नाते सरकार के बारे में सबसे अधिक जानकारीयां उनके पास होना स्वभाविक है। फिर पुलिस के तो तन्त्र की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह रहती है कि वह सरकार के आंख, कान और नाक की भूमिका पूरी ईमानदारी और सक्रियता से निभाये। चुनावों के दौरान तो सत्तारूढ़ दल सबसे अधिक विश्वास पुलिस की सूचनाओं पर करता है। सीआईडी चुनावों से पहले यह सर्वे तक करती है कि जनता का रूझान किस दल की ओर कितना है। ऐसे में जब पुलिस प्रमुख ही चुनावों से पहले ही केन्द्र मे जाने के प्रयासों में लग जाये तो स्वभाविक है कि इस पर चर्चाएं तो उठेंगी ही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिन्हें आगे बढ़ाने के लिये पुलिस की राय ली गयी होती है। ऐसे मामलों का चुनावों पर प्रभाव भी पड़ता है। चर्चा है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो मामला दर्ज किया गया था वह दो मन्त्रीयों और कुछ पुलिस अधिकारीयों के दवाब में ही लिया गया फैसला था। मुख्यमन्त्री शायद इस पक्ष में नही थे। इसी तरह कुल्लु में एक मामला दर्ज हुआ। चर्चा है कि सीआईडी यह मामला दर्ज करने के पक्ष नहीं थी और पुलिस ने फिर भी यह मामला दर्ज कर लिया। ऐसे मामले जब भी देर – सवेर अदालत में पहुंचते हैं तब वह फिर चर्चा में आ जाते हैं। तब फिर नेतृत्व पर सवाल आते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आने वाले दिनों में चर्चा के विषय बनेंगे।

इस परिदृश्य में इन वरिष्ठ अधिकारीयों का दिल्ली जाने के लिये आवेदन करना राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय होना स्वभाविक हो जाता है क्योंकि अभी सरकार ने मण्डी और धर्मशाला क्षेत्र में दो मीडिया कोआर्डिनेटर नियुक्त किये हैं। यह नियुक्तियां भी अब सरकार के चौथे वर्ष में हुई हैं। इन नियुक्तियों से भी यही संदेश जाता है कि सरकार का सूचना और जन संपर्क विभाग भी शायद सरकार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उत्तर पाया है इसीलिये उपचुनावों से पहले इन नियुक्तियों को अंजाम दिया गया है। अभी मण्डी, कांगड़ा और शिमला लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इन्ही को ध्यान में रखकर इन्ही क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले पत्रकारों को यह नियुक्तियां दी गयी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनो में शिमला और हमीरपुर के क्षेत्रों में भी ऐसी ही नियुक्तियां की जायेंगी।

किसी भी सरकार के लिये पुलिस और सूचना एवम् जन संपर्क विभाग चुनावी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे में जब इन्हीं विभागों में चुनावों से पहले इस तरह की स्थितियां बनना शुरू हो जायें तो उसके कई अर्थ लगने शुरू हो जाते हैं। फिर इस समय तो भाजपा केन्द्र से लेकर राज्यों तक सभी जगह परफारमैन्स को लेकर लगातार आकलनों मे जुट गयी है। केन्द्र के मन्त्रीमण्डल में फेरबदल के दौरान एक दर्जन मन्त्रीयों की छुट्टी किया जाना उत्तराखण्ड में मुख्यमन्त्री का बदलना और अब कर्नाटक में मुख्यमन्त्री बदलने की कवायद शुरू होना इसी आकलन के परिणाम माने जा रहे हैं। हिमाचल में भी इसी आकलन के लिये शिमला और धर्मशाला में पांच दिन तक कोर कमेटी का मन्थन चला था। इस मंथन में 2017 में जिन 68 लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन सबको बुलाया गया था। इस बैठक में हुई चर्चा के बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ और केन्द्र को सौंपा गया उसमें बड़े पैमाने पर नॉन – परफारमैन्स आयी है। यह नॉन परफारमैन्स ही इस समय केन्द्र के सामने बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिये पुलिस और सूचना एवम् जन संपर्क विभागों में चल रही गतिविधियां विश्लेष्कों के लिये महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

क्या प्रदेश में हो रहे हैं महिला मुख्यमन्त्री लाने के प्रयास

शिमला/शैल। इस समय भाजपा शासित किसी भी राज्य में महिला मुख्यमन्त्री नहीं है। केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल के फेरबदल मे इस बार महिलाओं को अधिमान दिया गया है। लेकिन कोई भी महिला मुख्यमन्त्री न होना भाजपा हाई कमान में सूत्रों के मुताबिक चिन्ता और चिन्तन का विषय बना हुआ है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की जब शिमला और धर्मशाला में मन्थन बैठक हुई थी और उसमें सरकार तथा संगठन के काम काज का आकलन हुआ था। तब उसी दौरान दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा प्रदेश से राज्य सभा सांसद महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामन्त्री इन्दु गोस्वामी में भी एक बैठक हुई थी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक के बाद तैयार हुई रिपोर्ट कार्ड में बड़े पैमाने पर नान परफारमैन्स का जिक्र हुआ है यह बाहर आ चुका है। इसी के साथ जलशक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह के कुछ ब्यानों ने भी विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार की वर्किंग को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। प्रदेश के 47 कॉलिजों में नियमित प्रिंसिपल नहीं है। एचपीएमसी के परवाणु प्लांट से 60 लाख के जूस के गायब पाये जाने पर अभी कोई कारवाई सामने नहीं आयी है। परिवहन निगम द्वारा दो सौ बसें खरीदने का प्रयास किया जाना जबकि फील्ड से इस तरह की कोई मांग न आयी हो। बल्कि पहले से खरीदी हुई कई बसें अभी तक ऑपरेशन में ही नहीं आ पायी हैं। निगम में ड्राईवरों और परिचालकों के कई पर रिक्त हैं। सेवनिवृत कर्मीयों को पैन्शन आदि का नियमित भुगतान न हो पाने पर यही कर्मी पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से अपनी समस्या सरकार और निगम प्रबन्धन के सामने रख चुके हैं। ऐसे हालात में भी नयी बसें खरीदने की कवायद करना सरकार की नियत और नीति पर सवाल उठायेगा ही। ऐसी वस्तुस्थिति जब हाई कमान के संज्ञान में आयेगी तो निश्चित रूप से इसका कड़ा संज्ञान लिया ही जायेगा।

सूत्रों की माने तो हाई कमान के सामने यह सारे मुद्दे आ चुके हैं। कोर कमेटी की बैठक के बाद जब प्रवक्ता ने नेतृत्व के प्रश्न पर जवाब दिया था उस जवाब पर भी शायद बीएल सन्तोष ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। प्रदेश की इन परिस्थितियों के परिदृश्य में अब जब मुख्यमन्त्री दिल्ली गये थे तब यह चर्चा फैल गयी थी कि शायद हाई कमान प्रदेश में महिला मुख्यमन्त्री लाने का प्रयोग करने जा रहा है। इस प्रयोग में इन्दु गोस्वामी का नाम सामने आया था। कांगड़ा में तो यह चर्चा बहुत जोरों पर थी बल्कि सचिवालय तक भी आ पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक इन्दु गोस्वामी के संज्ञान में भी यह सब रहा है और उन्होंने ऐसी चर्चाओं का कोई खण्डन भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान महिला मुख्यमन्त्री लाने का गंभीरता से विचार कर रहा है। यह प्रयोग हिमाचल में किया जाता है या किसी अन्य प्रदेश में इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में यदि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर अपनी टीम में नॉन परफार्मरज़ के खिलाफ कोई कदम नही उठा पाते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ कठिनाईयां बढ़ना तय है। वैसे इस नॉन परफार्मिंग का पता इन आने वाले उपचुनावों में लग जायेगा।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ

शिमला/शैल। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

मुख्य सचिव अनिल खाची ने नियुक्ति वारंट पढ़ा। राज्यपाल के सचिव प्रियातु मंडल ने प्रभार प्रमाण-पत्र पर राज्यपाल के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल, विधायकगण, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश पी.एस. राणा, मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय शर्मा, महापौर सत्या कौंडल, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, विभिन्न आयोग, बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

इसके पश्चात् मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह प्रदेश सरकार की विकास की पहल को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह संविधान का उच्च पद है और वह प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के समृद्ध पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम मिलकर कार्य करेंगे।

आर्लेकर ने कहा कि वह प्रदेश के लोगों के आतिथ्य सत्कार से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि गोवा लिबरेशन मूवमेंट में हिमाचल प्रदेश के कई लोगों ने अपना योगदान दिया जिनमें राम सिंह एक थे। वह उनके परिजनों से मिलने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करने से पहले परिवार के सदस्यों के साथ यज्ञ में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में आयी बाढ़ की घटनाओं से अवगत करवाया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। शिष्टाचार

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को हाल ही में विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ की घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने जानकारी दी कि जिला प्रशासन एनडीआरएफ के सहयोग से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। जिन लोगों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया।

राज्यपाल ने इस प्राकृतिक आपदा के मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं।

कौशल विकास निगम के माध्यम से पर्यटन, आतिथ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को मिले प्रशिक्षण:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में कौशल विकास निगम की बैठक की

अध्यक्षता की। उन्होंने पोस्ट कोविड प्रबंधन कार्यक्रमों पर जोर देते हुए स्वास्थ्य संबंधी भूमिकाओं जैसे आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन, सामान्य ड्यूटी सहायक (जीडीए), जीडीए गंभीर रोगियों की देखभाल, गृह स्वास्थ्य सहायता, चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी सहायता आदि पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि उद्योग की आवश्यकताओं को समेकित किया जाए और सभी पात्र उम्मीदवारों को अवसर दिए जाएं तथा युवाओं को ऑक्सीजन रिफिल स्टेशनों व ऑक्सीजन संयंत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण संरचनाओं और प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आर्लेकर ने कहा कि कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवं आतिथ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रिम प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी ग्रामीण आजीविका केंद्रों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने निगम द्वारा की गई पहल की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की दिशा में अधिक काम करेगा।

निगम की महाप्रबंधक नीरज चंदला ने राज्यपाल को निगम की गतिविधियों से अवगत करवाया और पावरवइंट प्रस्तुति देते हुए कहा कि इसे वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्य कौशल मिशन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि यह राज्य भर में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए एक छत्र निकाय है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से निगम राज्य में तकनीकी व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण (टीवीईटी) ढांचे को मजबूत करता है और राज्य में गुणवत्ता कौशल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में युवाओं के लिए मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण और हिमाचली युवाओं के लिए एचपीकेवीएन द्वारा प्रायोजित शत-प्रतिशत प्रशिक्षण लागत उपलब्ध करवाना है।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने की राशि शीघ्र अधिसूचित होगी

शिमला/शैल। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रीमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वे सड़क पर सुरक्षा एवं यातायात नियमों का गंभीरता से पालन कर सरकार के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें, ताकि नियमों की उल्लंघना से होने वाली क्षति पर अंकुश लग सके और ट्रैफिक नियमों की अनुपालना न करने पर होने वाली जुर्माने की राशि से असुविधा न हो।

आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 में संशोधन के लिए नियम बनाकर आबकारी एवं कराधान विभाग को राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस नियम को हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 (164वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD, Palampur on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table:-

Sr.No. Name of Work	Estimated cost	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid
1. Providing and fixing Brinze Bust of Dr. Bhim Rao Ambedkar at Palampur. (SW:- C/O Pedestals Statue)	Rs. 8,92,000/-	28.7.2021	Rs.17850/-	04.08.2021

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website **WWW.hptenders.gov.in**

Adv. No. 2507/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

PRESS NOTICE TO BE PUBLISHED IN NEWS PAPERS FOR OFFLINE TENDERS

The **Executive Engineer Jal Shakti Division Rampur invited tenders on behalf of the Governor of Himachal Pradesh** from approved eligible contractors for the following works(s) through offline process.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Time
1. Improvement of LWSS from Nogli Khad to Shingla , Uroo,Umri Kalna & Devtan etc. in GP Shingla Tehsil Rampur Distt. Shimla (HP) (SH:- Providing & Supplying of Cast steel valve following dia for Rising Main.	Rs.424540/-	Rs.8491/-	Rs. 250/-	One Month
2. A/R 7 M/O Sewerage scheme Sarahan in GP Sarahan Tehsil Rampur Distt. Shimla (HP) (SH:- Laying & Jointing of DI Pipe 150mm dia = 300 Rmt. and C/O 9 Nos. RCC Circular Man hole chamber and C/O 1 No. PCC Pillar	Rs.496272/-	Rs.9925/-	Rs. 250/-	Three Months
3. R/R Damages LIS Kumsu Piplidhar in GP Kumsu & Duttnagar Tehsil Rampur Distt. Shimla HP (SH:- Jackting of existing s/tank 11000 Ltr. Cap & 40000 Cap)	Rs.195965/-	Rs.3919/-	Rs. 250/-	Three Months
4. Prov. GWSS to Kartot in GP Gopalpur in Tehsil Rampur (SH:- L/J testing of GI pipe various dia at different Node to Provide FHTC to household) Job.No.2	Rs.497241/-	Rs.9945/-	Rs. 250/-	Three Months
5. Prov. GWSS to Kartot in GP Gopalpur in Tehsil Rampur (SH:- L/J testing of GI pipe various dia at different Node to Provide FHTC to household) Job.No.1	Rs.464686/-	Rs.9294/-	Rs. 250/-	Three Months

Last date of submission of tender **20.07.2021 upto 11.00 AM** and will be opened on same day **on 11.30 AM.**
Last date of sale of tender from Divisional Office **19.07.2021 upto 4.00 PM.** The tender forms and other detailed conditions can be downloaded from the website **www.iph.org** or from office of above Executive Engineer upto date specified above.

Adv. No. 2496/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

H. P. P.W.D. TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the **Executive Engineer Fatehpur Division HPPWD.,** Fatehpur on behalf of the Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD.

TENDER SCHEDULE:

1. **Date and time of receipt of application for tender form:** 20.08.2021upto 2.00 PM
2. **Date and time of issue of tender form:** 20.08.2021upto 5.00 PM
3. **Date and time of receipt of tenders:** 21.08.2021upto 10.30AM
4. **Date and time of opening of tenders:** 21.08.2021 at 11.00 AM

The tenders form will be issued against cash payment (non refundable). The earnest money in the shape of NSC/FDR/Deposit at call of any of Post Office/Bank in H.P duly pledged in the name of the **Executive Engineer, Fatehpur Division HPPWD** Fatehpur must accompany with each tender.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time limit	Cost of Form	Eligible Class of Contractor
1. Restoration of Rain Damages Bhatoli Phakwan Malhanta Chhatral road km. 0/0 to 8/765 (SH:- Repair of pot holes, providing and laying 20mm thick premix carpet with seal coat including Grading-3 in km. 7/250 to 7/765, 7/765 to 8/265 and 8/300 to 8/765).	Rs.499174/-	Rs.10000/-	One month	350/-	Class D&C

1. The contractors/firms should possess the following documents (Photocopy to be attached):
(i) The contractor/Firms should be enlisted with the HPPWD.
(ii) PAN (Permanent Account No.)
(iii) Registration under GST
(iv) Ambiguous/telegraphic/conditional tenders or tender by Fax/E-mail shall not be entertained /considered in any case.
(v) The Executive Engineer reserves the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reason(s).
(vi) Only two tenders shall be issued to each contractor.
(vii) The tender will not be issued to those contractors who have already two or more works in hand in HPPWD. The contractor will give an affidavit along with application that he has not more than two works in hand in HPPWD for execution, failing which the application for issuing the tender forms shall not be accepted.
(viii) Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which the case likely to be rejected.

Adv. No. 2426/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

प्रधानमंत्री ने राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन की सराहना की:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से 1810 करोड़ रुपये की 210 मेगावाट की लुहरी चरण-1 जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखने का भी आग्रह किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि इन दोनों पार्कों से न केवल राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सुनिश्चित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नागचला, मण्डी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित हवाई अड्डे का लिडार सर्वेक्षण किया जा चुका है और यह हवाई अड्डा न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर नजर रखे हुए है और उनसे कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होटल और होम-स्टे मालिकों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी इकाइयों में पर्यटकों का स्वागत करते समय उचित एहतियाती कदम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक वैक्सीन की 44.16 लाख खुराक दी जा चुकी हैं, जिसमें लगभग 10.45 लाख दूसरी खुराक भी सम्मिलित हैं।

प्रदेश में 17407 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया जाएगा: वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की चौथी बैठक की अध्यक्षता की और आयोग की प्रगति की समीक्षा की।

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों को सु ढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े हुए पशुओं को संरक्षण, पुनर्वास और आश्रय प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अनेक प्रयास कर रही है। अब तक सरकार ने 17407 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के मामले में हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने गौ सेवा आयोग के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल, 2021 से 13 जुलाय्र, 2021 से लगभग 12 करोड़ 44 लाख, जिसमें से आठ करोड़ 71 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि गौ सदन, गौशाला, गौ अभ्यारण्य सहायता योजना के अंतर्गत जो मार्च, 2021 से जून 2021 तक दो करोड़ 85 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जिसमें गौ सदन, गौशाला, गौ अभ्यारण्य को प्रत्येक गौवंश के भरण-पोषण के लिए हर महीने 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग द्वारा लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए शीघ्र एक वेबसाईट आरम्भ की जाएगी जिसमें अंशदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए :शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने फोरलेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए

गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार राइट-ऑफ-वे से सटी/बाहर भूमि पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व प्रदेश सरकार को मिलकर नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे प्रभावितों को तुरंत उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों का ब्यौरा एकत्रित करने और पुनर्वास नीति के अन्तर्गत मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाए।

गोविन्द सिह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मल्टीपलीकेशन फेक्टर को एक से अधिक करने के सम्बंध में संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को पांच मीटर कंट्रोल ब्रिडथ मामले में राहत प्रदान करने पर विचार करेगी। फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां बाईपास बनाकर उन्हें विस्थापित होने से बचाया जाए।

उन्होंने कहा कि सड़कें देश और प्रदेश की भाग्य रेखाएं कही जाती हैं। राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए ताकि इसे प्रदेश के लोग लाभान्वित हों।

प्रधान सचिव राजस्व के.के पंत, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग शुभाशीष पांडा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मेधा प्रोत्साहन योजना में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं को आरक्षित रहेगीं

शिमला/शैल। उच्चत्तर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश सरकार की मेध प्रोत्साहन योजना के अतंगर्त मेधावी विद्यार्थियों से हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों के संस्थानों से प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं जो कलैट, एनईईटी, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी, एनडीए आदि तथा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एवं बीमा और रेलवे इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के कार्य में कार्यरत हैं।

विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि चयनित विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्वेच्छा से किसी भी संस्थान से ऑनलाईन या व्यक्तिगत रुप से प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेने को स्वतन्त्र होंगे। इस योजना के अंर्तगत आवेदन के लिए विभाग ने विद्यार्थियों के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी विद्यार्थी की उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत जमा दो स्तर के 350 अभ्यार्थियों तथा स्नातक स्तर के 150 अभ्यार्थियों को मैरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। वर्तमान में जमा दो कक्षा में पढ़ रहे सामान्य वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के जमा एक कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्यपिछडा वर्ग/आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के विद्यार्थियों के कम से कम 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए। अभ्यार्थी के परिवार की कुल आय 2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम एक लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगीं तथा अन्य सीटें में आरक्षण सरकार के नियमों के अनुरूप रहेगा। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र सम्बंधित जिला के उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर के माध्यम से तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थी सीधे शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के कार्यालय में 24 जुलाई 2021 तक जमा करवा सकते है। आवेदन ई-मेल medha.protsahan@gov.in पर भी भेजी जा सकती है। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी विभाग की वैबसाइट www.educationhp. org पर उपलब्ध है।

मीडिया देश के मुख्य मुद्दों को जनता के समक्ष लाता है:डीजीपी

शिमला/शैल। समाज के विकास और उत्थान में मीडिया की अहम भूमिका है। मीडिया देश के

मुख्य मुद्दों को जनता के समक्ष लाता है। आज के दौर में मीडिया बहुत शक्तिशाली अंग बन गया है और ये समाज में नैरेटिव (आख्यान) सैट करता हैं। प्रेस क्लब शिमला की ओर से आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में डी.जी.पी. संजय कुंडू ने कही।

उन्होंने कहा कि मीडिया समाज में नैरेटिव सैट करने का भी काम करता है। देश के विकास, आर्थिक नीतियों और राजनीति में नैरेटिव सैट करने में मीडिया का रोल रहता है।

डी.जी.पी. ने कहा कि शिमला प्रेस क्लब एक शक्तिशाली संगठन है, जो कि प्रदेश का नैरेटिव सैट करता है। प्रदेश को आगे ले जाने में प्रेस क्लब भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि प्रेस क्लब में मीडिया के कई माइंड जुड़े होते हैं।

संजय कुंडू ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से सोशल मीडिया का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। सकारात्मक पहलू ये है कि सोशल मीडिया में तुरंत फीडबैक मिल जाती है। हालांकि 80 फीसदी फीडबैक नकारात्मक और 20 फीसदी फीडबैक सकारात्मक होती है। संजय कुंडू ने कहा कि सोशल मीडिया की सकारात्मक फीडबैक से पुलिस विभाग को अपने प्रदर्शन को आंकने और इससे पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने में मदद मिलती है। डीजीपी ने कहा कि एक साल पहले प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफार्म टविटर पर 12 हजार फोलोवर थे, जो अब बढ़कर 20 हजार हो गए हैं। इस दौरान संजय कुंडू ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और नई योजनाओं व प्राथमिकताओं की मीडिया प्रतिनिधियों की जानकारी दी।

इससे पहले प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने डीजीपी संजय कुंडू को हिमाचली टापी व मफलर देकर सम्मानित किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल हैडली ने एक स्मृति चिन्ह डीजीपी संजय कुंडू को भेंट किया। डीजीपी संजय कुंडू की तरफ से भी एक स्मृति चिन्ह प्रेस क्लब अध्यक्ष को भेंट किया गया।

राज्य में कोरोना के नए रूप के खिलाफ कोविशील्ड 94 प्रतिशत प्रभावी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन्साकॉग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोरोना का नया रूप डेल्टा, भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में पाया गया एक प्रमुख वेरिएंट है जो विश्वभर में तेजी से फैल रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी है।

जन स्वास्थ्य इंग्लैंड द्वारा वैक्सीन के प्रभाव को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड की दो खुराक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के खिलाफ 94 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगवाने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए।

प्रवक्ता ने बताया कि 1 से 16 जुलाई, 2021 तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिल कोरोना रोगियों के संबंध में किए गए विश्लेषण के अनुसार पिछले 16 दिनों में आईजीएमसी शिमला में कोरोना के सबसे अधिक मरीज दाखिल हुए हैं। गत 16 दिनों में आईजीएमसी में एक दिन में अधिकतम 20 कोविड मरीज भर्ती हुए हैं। उन्होंने बताया कि डॉ. वाईएस परमार राजकीय आयुविज्ञान महाविद्यालय नाहन में 11 जुलाई, 2021 तक 43 कोविड रोगियों को भर्ती किया गया था और तब से 16 जुलाई 2021 तक कोई भी कोविड मरीज भर्ती नही हुआ है।

प्रवक्ता ने लोगों से हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया।

दण्डनीति के प्रभावी न होने से मंत्रीगण भी बेलगाम होकर अप्रभावी हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या अपराधियों और करोड़पतियों के हाथों जनहित सुरक्षित रह सकते हैं

केन्द्र में जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक करीब तीन सौ मामले देशद्रोह के दायर हुए हैं। इन मामलों में करीब पांच सौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परन्तु अदालत में केवल नौ लोगों को ही दोषी करार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज आज़ादी के बाद भी देशद्रोह के कानून को चलाये रखने पर हैरानी व्यक्त की है। केन्द्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। जब यह मामला अदालत में पहली बार सुनवायी के लिये आया तब अटार्नी जनरल ने यह कहा है कि अभी इस प्रावधान को खत्म नहीं किया जाना चाहिये। सरकार इस पर क्या जवाब देती है और अदालत का इस पर क्या फैसला आता है यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान से इस पर एक बड़ी बहस की शुरूआत अवश्य हुई है। जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले बनाये गये हैं उनमें अधिकांश में बुद्धिजीवि और पत्रकार रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ यह मामले बनाये जाने का आधार प्राय: किसी भी विषय पर सरकार से भिन्न राय रखना या सरकार से तीखे सवाल पूछना रहा है। इससे यही स्पष्ट होता है कि इस सरकार में शायद वैचारिक मत भिन्नता के लिये कोई स्थान नही है। जब कोई सरकार यह मान लेती है कि जनहित को लेकर उससे बेहत्तर सोचने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है तब जब भी मत भिन्नता का कोई सवाल सामने आ जाता है तब वह अस्वीकार्य ही नहीं बल्कि देशद्रोह करार दे दिया जाता है। सरकार से भिन्न राय रखना आज देशद्रोह बनता जा रहा है। अभी जिस तरह से ईज़रायल की ऐजैन्सी के माध्यम से पत्रकारों, जजों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने का प्रकरण सामने आया है। उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि सवाल पूछने का साहस रखने वालों से सरकार किस कदर परेशान है। अभी संसद का सत्र चल रहा है और पहले ही दिन यह जासूसी प्रकरण सामने आ गया है। संसद में इस पर किस तरह के सवाल उठते हैं और सरकार का जवाब क्या रहता है यह देखना दिलचस्प होगा।

इस समय देश में महंगाई और बेरोज़गारी दोनों अपने चरम पर रहे हैं। यह सब सरकार की नीतियों का परिणाम है। यदि सरकार की नीतियों पर सवाल न भी उठाया जाये तो क्या यह मंहगाई और बेरोज़बारी समाप्त हो जायेगी? क्या इससे सिर्फ सरकार से मत भिन्नता रखने वाले ही प्रभावित हैं और दूसरे नहीं? हर आदमी इससे प्रभावित है लेकिन सरकार से सहमति रखने वालों की प्राथमिकता हिन्दुत्व है। हिन्दुत्व के इस प्रभाव के कारण यह लोग यह नही देख पा रहे हैं कि इन नीतियों का परिणाम भविष्य में क्या होगा? मंहगाई और बेरोज़गारी का एक मात्र कारण बढ़ता निजिकरण है? 1990 के दशक में निजिक्षेत्र की वकालत में सरकारी कर्मचारी पर यह आरोप लगाया गया था कि वह भ्रष्ट और कामचोर है। तब कर्मचारी और दूसरे लोग इसे समझ नही पाये थे। इसी निजीकरण का परिणाम है कि एक-एक करके लाभ कमाने वाले सरकारी अदारों को बड़े उद्योगपतियों को कोड़ियो के भाव में बेचा जा रहा है। यही नहीं इन उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का कर्ज देकर उन्हें दिवालिया घोषित होने का प्रावधान कर दिया गया है। इस दिवालिया और एनपीए के कारण लाखों करोड़ बैकों का पैसा डूब गया है बैंकों ने इसकी भरपायी करने के लिये आम आदमी के जमा पर ब्याज घटा दिया है। सरकार अपना काम चलाने के लिये मंहगाई बढ़ा रही है क्योंकि उससे टैक्स मिल रहा है। इसी के लिये तो मंहगाई और जमाखोरी पर नियन्त्रण करने के कानून को ही खत्म कर दिया गया है।

आज जिस तरह के संकट से देश गुजर रहा है उस पर संसद में कितनी चिन्ता और चर्चा हो सकेगी इसको लेकर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज की संसद तो अपराधियों और करोड़पतियों से भरी हुई है। इस समय लोकसभा में ही 83% सांसद करोड़पति है। 539 में से 430 करोड़पति है। इन्हीं 539 सांसदों में 233 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 159 के खिलाफ तो गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। 2014 में 542 में से 185 के खिलाफ मामले थे और 2009 में केवल 162 के खिलाफ मामले थे। जिस संसद में करोड़पतियों और अपराधियों का इतना बड़ा आंकड़ा हो वहां पर आम गरीब आदमी के हित में कैसे नीतियां बन पायेंगी यह अन्दाजा लगाया जा सकता है। मोदी ने कहा था कि वह संसद को अपराधियों से मुक्त करवायेंगे। परन्तु यह आंकड़े गवाह है कि उनके नेतृत्व में 2009 से 2014 में और फिर 2019 में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया है। आज तो मन्त्रीमण्डल में गृह राज्य मन्त्री ग्यारह आपराधिक मामले झेलने वाला व्यक्ति बन गया है। इस परिदृश्य में अब यह आम आदमी पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या सोचता और करता है क्योंकि उसी के वोट से यह लोग यहां पहुंचे हैं।

ट्विटर, पीएफआई को सामाजिक आधार प्रदान कर देश की सुरक्षा में लगा है सेंध

गौतम चौधरी

ट्विटर ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) कर्नाटक चैप्टर के ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक दिया है। आइए सबसे पहले ट्विटर का ब्लू टिक क्या है, उसको समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ट्विटर-एक लोकप्रिय सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग व्यक्तियों/ संगठनों द्वारा आभासी सार्वजनिक स्थान पर अपने विचारों, विचारधाराओं का प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। किसी भी हैंडल (ट्विटर अकाउंट) से जुड़ा एक ब्लू टिक खाते को वैधता ही प्रदान नहीं करता है अपितु यह एक प्रकार का प्रमाण-पत्र होता है कि जो तथ्य आभासी सोशल साइट पर डाला गया वह पूर्ण सत्य है और उसका सत्यापन ट्विटर प्रबंधन जानकारों की टीम के द्वारा किया जा चुका है। मसलन, इसे ट्विटर द्वारा 'सत्यापित' करार दिया गया है। प्रचार पाने के लिए ट्विटर प्रबंधन से व्यक्तियों/ संगठनों के द्वारा ब्लू टिक की अमूमन मांग भी की जाती है।

पीएफआई के कर्नाटक चैप्टर के एकाउंट को ब्लू टिक देकर ट्विटर ने न केवल भारतीय सुरक्षा एजेंशियों को को चुनौती दी है अपितु भारतीय समाज के आपसी संबंधों को बिगाड़ने की भी कोशिश की है। यह न तो व्यवसाय की नैतिकता है और ही सामान्य नैतिकता पर खड़ा उतरता है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश के बुद्धिजीवियों, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों और देश एवं समाज की सुरक्षा के लिए चिंतित राष्ट्रवादियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देश की एकता और अखंडता के प्रति सजग सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर संज्ञान भी लिया है। हालांकि कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि एक मात्र प्रतीक पर यह हंगामा क्यों है लेकिन उन लोगों को यह समझना चाहिए कि आभासी दुनिया में इस प्रकार की बातें अब बहुत महत्व रखने लगी है। जब से मामला सामने आया है, ट्विटर के प्रति आशंकाएं बढ़ने लगी है। ट्विटर प्रबंधन पीएफआई के निर्णय को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है साथ ही यह भी साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार की ही गलती है। जबकि सत्यता इससे कई मील दूर है।

बता दें कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के इशारे पर बेंगलुरु में हिंसा हुई थी। धार्मिक असहिष्णुता के कारण हुई हिंसा इतनी तीव्र थी कि इसने पूरे पुलिस थाने को नष्ट कर दिया और करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया। इससे पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों की मंशा साफ-साफ दिख रही है।

अपहरण से लेकर राजनीतिक हत्याओं तक, पीएफआई न केवल पूरे भारत में, बल्कि सीरिया सहित मध्य पूर्व के कई देशों में बदनाम है। यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहता है। यह भारत में आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन के लिए लड़ाके उपलब्ध कराता रहा है। इसकी गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर एनआईए जांच भी कर रही है।

पीएफआई प्रचार पाने और सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक वैमनस्यता भड़काने के लिए भी जाना जाता है। अभी हाल ही में पदम वन क्षेत्र में केरल के वन अधिकारियों द्वारा की गई एक अनुसंधान ने चौकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। पीएफआई वहां अपने कैडरों को आईईडी और बम बनाने का प्रशिक्षण दे रहा था।

ऐसे समय में जब ट्विटर भारतीय संघ के द्वारा बनाए गए नए संशोधित आईटी अधिनियम का पालन करने में आना-कानी कर रहा है, तब इस प्रकार की गतिविधि ट्विटर प्रबंधन की नैतिकता और तटस्थता पर सवाल खड़े कर देता है। एक घोषित चरमपंथी संगठन के पोस्ट पर ब्लू टिक देने का ट्विटर का निर्णय संदेह पैदा कर रहा है। सरकार देश के हित को ध्यान में रखते हुए ट्विटर से जवाबदेही चाहती है लेकिन ट्विटर देश के कानूनों को ठेंगा दिखाने पर आमादा है। यह स्वतंत्रता कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है।

पीएफआई जैसे संगठनों को वैधता प्रदान करके, ट्विटर ने साबित कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया दिग्गजों की गतिविधियों की जांच के लिए नए कानूनों की आवश्यकता है। अब हम फिर इस सवाल पर वापस आते हैं कि महज ब्लू टिक से एक चरमपंथी संगठन के हिंसक अतीत को भुला दिया जाएगा और उसे वैध मान लिया जाएगा? इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक ही होगा। आखिरकार, वर्षों से हिंसा में संलिप्त इस संगठन को मात्र रंगों के प्रतीक से वैध नहीं ठहराया जा सकता है। ट्विटर को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही ट्विटर जैसे आभासी दुनिया के दिग्गज सामाजिक प्लेटफार्म को यह समझना चाहिए कि इस प्रकार के चरमपंथी संगठन किसी के लिए हितकारी नहीं होते हैं।

हिमाचल सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित हो रहा जनजातीय क्षेत्रों का तीव्र विकास

शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के समान एवं संतुलित विकास और जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति अपने दृढ़संकल्प पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कई पहले की है जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों का तेजी के साथ विकास हो रहा है।

प्रदेश में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5.71 प्रतिशत है और इस समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल राज्य योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हांकित है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आकार वर्ष 2018-19 में 567 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 639 करोड़ रुपये जबकि वर्ष 2020-21 में 711 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 846.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 25.95 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से व 2.88 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से के रूप में, 2019-20 में 27.50 करोड़ रुपये केन्द्रीय व 3.05 करोड़ रुपये राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्रदान किये गए। वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से और 2.78 करोड़ रुपये का राज्य के अंश के रूप में प्रावधान किया गया है।

जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन, सड़कों एवं पुलों और भवन निर्माण पर वर्ष 2018-19 के दौरान 127.69 करोड़ रुपये, 2019-20 में 147.33 करोड़ रुपये, 2020-21 के दौरान 195.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 244.06 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम- 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निर्धारित 7095 लक्ष्यों के विरुद्ध 8669 जबकि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 6829 लक्ष्यों के मुकाबले 7509 लक्ष्यों की प्राप्ति हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर में टैलीमेडिसन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 200 लाख रुपये, 2019-20 में 174 लाख रुपये और 2020-21 में 193 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2021-22 में 84 लाख रुपये प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान तीन नए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल भरमौर, पांगी ओर लाहौल में खोलने की स्वीकृति प्रदान की जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से आरम्भ कर किया दिया है। केंद्र सरकार से इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए अब तक 32 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रदेश में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कार्यशील हैं जिनमें 554 अनुसूचित जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को जनजातीय क्षेत्रों व गैर-जनजातीय क्षेत्रों में तीव्र गति से क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। प्रदेश के पंचायत चुनावों के उपरान्त जिला व उप-मंडल स्तरीय समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अब तक पांच जिला स्तरीय एवं 35 उप-मण्डल स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर 17,503 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है।

प्रदेश में अभी तक 1918.9369 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन अधिकारी और 2.4129 हेक्टेयर वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार चिन्हित व निहित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र लाहौल व पांगी के लिए रोहतांग अटल टनल का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नया आयाम मिला है।

स्पिति (काजा) में समुद्र तल से 12040 फीट की ऊंचाई पर युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन द्वारा प्रथम बुनियादी आइस हॉकी प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया गया।

फिर से विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन– भारत का गौरव

यह विकसित रेलवे स्टेशन, भारत के अन्य रेलवे स्टेशनों के लिए विकास के मानकों को रेखांकित करता है। –एस.के. लोहिया, एमडी और सीईओ आईआरएसडीसी–

शिमला। भारत का पहला पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है–गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जो गुजरात राज्य में स्थित है और जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। फिर से विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की एक लम्बी छलांग के रूप में देखा जा रहा है।

नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, ''यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है।'' यह कथन, स्टेशन पुनर्विकास के सन्दर्भ में उपयुक्त है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ, देश में सम्पूर्ण स्टेशन परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसा कि सैंटियागो कालात्रावा ने कहा है, ''स्टेशन एक ऐसी चीज है, जो एक शहर का निर्माण कर सकती है।'' गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शहर को बढ़ावा देने वाले घटकों के रूप में कार्य करेगा, निवेश चक्र का निर्माण करेगा, नौकरी के अवसरों का सृजन करेगा और मोटे तौर पर गुजरात राज्य की राजधानी, गांधीनगर की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

यह एक अनूठी परियोजना है, जिसमें आईआरएसडीसी (भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम) के माध्यम से गुजरात सरकार और रेल मंत्रालय की साझेदारी में गरुड़ (गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास निगम) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है।

इस पुनर्विकसित स्टेशन में पटरियों के ऊपर 318 कमरों वाला फाइव स्टार कन्वेंशन होटल है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो मुंबई और बेंगलुरु जैसे भूमि की कमी झेल रहे शहरों में इस तरह के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। गांधीनगर में पहले से ही 'महात्मा मंदिर' है, जो विश्व स्तरीय सम्मलेन और प्रदर्शनी केंद्र है। इसे होटल और रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ा गया है, ताकि ये सुविधाएं एक दूसरे के साथ तालमेल से काम कर सकें। यह होटल, कन्वेंशन सेंटर के लिए लॉजिस्टिक्स को आसान बनाएगा तथा इसके बेहतर उपयोग में मदद करेगा। ठीक इसी तरह कन्वेंशन सेंटर भी होटल के बेहतर उपयोग में सहायता प्रदान करेगा। कन्वेंशन सेंटर में अधिक आयोजनों से होटल उद्योग, खान–पान और पर्यटन के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। हेलीपैड प्रदर्शनी मैदान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित दांडी कुटीर संग्रहालय निकट में ही स्थित हैं, जिन्हें इन नयी परियोजनाओं से प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। गरुड़ और आईआरएसडीसी ने इस पुनर्विकसित स्टेशन के साथ–साथ आसपास के क्षेत्रों में और अधिक सुविधाएं जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि स्थानीय क्षेत्र को और बढ़ावा मिल सके तथा इसे सभी क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुरुचिपूर्ण गंतव्य बनाया जा सके।

दो नई ट्रेन 16 जुलाई 2021 से शुरू की जा रही हैं। पहली वाराणसी के लिए एक साप्ताहिक सुपरफास्ट और दूसरी वरेथा के लिए एक दैनिक मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही है। इस क्षेत्र के लिए रेल मंत्रालय के पास कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और चूंकि गांधीनगर क्षेत्र को स्टेशन के पुनर्विकास की इन पहलों के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, इसलिए अधिक ट्रेन सेवाएं शुरू की जा सकती हैं।

पुनर्विकसित स्टेशन सात सी के सिद्धांतों का पालन करता है जो आईआरएसडीसी द्वारा पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों की योजना बनाने के लिए मूल सिद्धांत हैं।

यात्रियों को अलग–अलग करने के लिए, प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए कॉनकोर्स और आने वाले यात्रियों के लिए दो सबवे तैयार करने की योजना बनाई गई है। स्टेशन भविष्य के लिए तैयार है, और स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए कॉनकोर्स का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, निकट भविष्य में, यात्रियों के साथ–साथ स्थानीय जनता की मांगों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में खुदरा, भोजन और मनोरंजन के आउटलेट खोलने की योजना है। बिग बाजार और शॉपर्स स्टॉप जैसे बाजार के संचालकों ने भी अपने मिनी आउटलेट खोलने में रुचि दिखाई है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए स्टेशन पर खरीदारी करना सुविधाजनक हो गया है। यह पुनर्विकसित स्टेशन एक 'सिटी सेंटर रेल मॉल' की तरह काम करेगा जिसके विभिन्न कार्यों में से एक यात्रा से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करना भी होगा।

दिव्यांगजनों के लिए स्टेशन, एक सुलभ वातावरण प्रदान करता है और सभी स्थानों पर लिफ्ट और रैंप उपलब्ध हैं। टैक्टाइल फ्लोरिंग जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। स्टेशन आधुनिक सुविधाओं जैसे पर्याप्त प्रतीक्षा स्थान, धूप/बारिश आदि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्तंभ रहित छत के माध्यम से, वातानुकूलित बहुउद्देशीय प्रतीक्षालय, शिशु आहार कक्ष, उन्नत संकेत और आधुनिक शौचालय, आम आदमी के लिए अंतरधार्मिक प्रार्थना कक्ष आदि से सुसज्जित है। अन्य सुविधाएं जैसे आर्ट गैलरी, थीम आधारित प्रकाश व्यवस्था, अतिरिक्त आकर्षण प्रदान करेगी जो न केवल यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाएगी बल्कि सभी के लिए गर्व का विषय भी साबित होगी क्योंकि यह स्टेशन देश में कई मायनों में प्रथम होने का दावा कर सकता है। भीड़ के बिना, पुनर्विकसित स्टेशन को पीक ऑवर में 1,500 यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कॉनकोर्स के साथ, पीक आवर में क्षमता 2,200 यात्रियों तक पहुंच जाएगी।

स्टेशन का उद्देश्य पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट, "लाई ऐश ईंटों आदि जैसी टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण का संरक्षण करना और ऊर्जा कुशल डिजाइनों, वर्षा जल संचयन और पानी के पुनःउपयोग के माध्यम से पानी, बिजली की आवश्यकताओं को कम करना है।

'इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी)' मॉडल पर बनाया गया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के लिए इस मॉडल को अपनाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन है। पुनर्विकसित स्टेशन पर अपनी तरह का अनूठा, स्तंभ मुक्त चिकना और किफायती स्पेस फ्रेम 99–मीटर (105 मीटर कर्विलिनियर) स्पैन ओवर प्लेटफॉर्म (भारतीय रेलवे में सबसे लंबा ऐसा स्पैन जिसमें केवल 120 किलोग्राम/वर्गमीटर इस्पात शामिल है) हर मौसम में सुरक्षित सीमलेस एल्युमिनियम शीटिंग के साथ प्रदान किया गया है। सबवे उपलब्ध कराना, ऊंची इमारत को सहारा देने के लिए बड़ी नींव और रूफ ट्रस के माध्यम से लॉन्च करना अद्वितीय इंजीनियरिंग चुनौतियां थीं जिन्हें कार्य के निष्पादन के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। वास्तव में, इस परियोजना से मिली सीख हमें शहरों के भीड़–भाड़ वाले इलाकों में ऐसी जटिल परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करने वाली है और इस परियोजना का प्रभाव दूर–दूर तक होगा।

32 थीम के साथ हर रोज एक थीम पर आधारित प्रकाश व्यवस्था का आयोजन गांधीनगर स्टेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह भारतीय रेलवे में इस तरह की सुविधा के साथ अब तक का पहला स्टेशन है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की योजना के अनुसार थीम आधारित प्रकाश व्यवस्था की विशेषता का उद्देश्य इस पुनर्विकसित स्टेशन का व्यापक रूप में उपयोग करना है। एलईडी लाइट्स का उपयोग स्टेशन की इमारत को खूबसूरत तरीके से दिखाने और सूर्यास्त के बाद इस इमारत की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हर रोज रंग बदलने के मुताबिक किया गया है। इस स्थल को आम आदमी के लिए एक गंतव्य स्थल बनाने के लिए डांसिंग लाइटों का उपयोग किया जाएगा। जब स्टेशन की लाइट इसके सामने स्थित दांडी कुटीर और इसकी पृष्ठभूमि में अहमदाबाद/गांधीनगर क्षेत्र की 77 मीटर की सबसे ऊंची इमारत को प्रकाशवान करेगी तो इसकी छटा देखने लायक होगी। गांधीनगर की जनता और दांडी कुटीर आने वाले पर्यटक इस पुनर्विकसित स्टेशन के आस–पास के क्षेत्र में विकसित की गई हरित पट्टी के विहंगम दृश्य का अवलोकन कर सकेंगे।

इसके साथ–साथ इन विकास कार्यों में, 'क' रोड को 'ख' रोड से जोड़ने के लिए बनाए गए नए 18 मीटर चौड़े अंडरपास के साथ–साथ गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग द्वारा महात्मा मंदिर और रेलवे स्टेशन के निकट के होटल का निर्माण इस क्षेत्र का कायापलट कर देगा, जो अब तक अधिकांश तौर पर एक जीवंत स्थल की जगह एक निर्जन स्थान था। यह स्थल अब इस शहर का एक ऐसा केंद्र होगा जहां गांधीनगर के लोग न केवल घूमने अपितु अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए जाना पसंद करेंगे। इस विकास का उद्देश्य स्टेशन के आसपास के पूरे क्षेत्र को शहर के एक ऐसे स्थल के रूप में परिवर्तित करना है जहां गांधीनगर के लोग जाना पसंद करेंगे, और जिस पर उन्हें गर्व होगा।

गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के साथ, स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम में समग्र रूप से तेजी आई है। कई और स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना हैं। इस अभियान के तहत 125 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है। इसमें से, आईआरएसडीसी 63 स्टेशनों पर कार्य कर रहा है, और आरएलडीए 60 स्टेशनों पर कार्य कर रहा है, जिसमें दो स्टेशन क्षेत्रीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। रियल एस्टेट विकास के साथ–साथ 123 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए कुल निवेश 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है। आईआरएसडीसी के तौर पर हम भारत सरकार के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्य अत्यंत उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ संचालित करेंगे। इस कार्यक्रम में रेलवे से यात्रा करने वाले आम आदमी की सेवा के लिए अभिनव दृष्टिकोण और समाधान की आवश्यकता है, जिसे हाल ही में विकसित किए गए गांधीनगर कैपिटल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रदर्शित किया गया है।

इस कार्यक्रम के लिए न केवल रेलवे स्टेशनों अपितु बड़े पैमाने पर शहरों और देश के आत्मानिर्भर भारत की ओर बढ़ने के संकल्प और कायाकल्प में सहायता के लिए सार्वजनिक और निजी साझेदारी परियोजनाओं में निर्माणकर्ताओं, निर्माता, अनुबंधकर्ताओं, योजनाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, खुदरा विक्रेताओं, विज्ञापनदाताओं, और सबसे महत्वपूर्ण, निवेशकों/डेवलपर्स के समर्थन और सक्रीय भागीदारी की आवश्यकता है।

मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल सुधार

–डॉ. नीलम महेंद्र–

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का ताज़ा विस्तार जहां कई उम्मीदों को जगाता सा दिखता है वहीं वो अपनी कई नाकामियों पर पर्दा डालता भी नज़र आता है। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के कई दिग्गजों से इस्तीफा लेकर नए चेहरों को सरकार में जगह दी गई है उससे इसे मंत्रिमंडल विस्तार न कहकर मंत्रिमंडल सुधार कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा।

इतना ही नहीं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेन्स के मंत्र पर चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है और इसी के साथ मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या 78 तक पहुंच गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार ने कई प्रश्न उत्पन्न किए हैं तो कई संदेश भी दिए हैं।

दअरसल कोरोना काल की शुरुआत में या फिर कोरोना की पहली लहर के दौरान जब कोरोना के कारण पूरे विश्व में तबाही मची हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि भारत ने कोरोना को काबू में कर लिया है।

अपने सीमित संसाधनों और विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत खुद को कोरोना की तबाही से बचाने में कामयाबी हासिल करके सम्पूर्ण विश्व को चौंका चुका था। मोदी सरकार मोदी ब्रांड बन चुकी थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर समुद्र में उठी सुनामी की वो लहर साबित हुई जिसने वर्तमान सरकार की कार्यक्षमता और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उस ब्रांड पर ही पानी फेर दिया।

जिस प्रकार से देश में साधारण एंटीबायोटिक से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी हुई या फिर ऑक्सीजन की कमी से हज़ारों जानें गईं और अस्पतालों में बिलों के द्वारा लूट का उपक्रम शुरू हुआ, आम आदमी के मन में प्रश्न उठने लगा था कि इस देश में प्रशासन नाम की कोई चीज़ भी है या फिर जंगल राज है।

यह सब विशेष रूप से इसलिए भी निराशाजनक था क्योंकि आम आदमी के साथ यह सब उस सरकार के शासन काल में हो रहा था जिस सरकार को उसने बेहद उत्साह और उम्मीदों के साथ दूसरी बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ मौका दिया था। शायद आम जनमानस के हृदय में उपजी यही निराशा इस मंत्रिमंडल विस्तार के अनेक कारणों में से एक कारण रहा हो। क्योंकि मोदी जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ यह अच्छी तरह जानता है कि नोटबन्दी या जीएसटी या फिर पेट्रोल डीज़ल की बढ़ती कीमतों जैसे विषयों में भले ही लोग अपने नेता की नीयत देखेते हों लेकिन जब बात आम आदमी के जीवन, उसके स्वास्थ्य, उसके अस्तित्व पर ही आ जाती है तो वो ही जनमानस नीयत नहीं नतीजे देखता है और कोरोना काल के निराशाजनक नतीजे किसी से छिपे नहीं है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में स्वास्थ्य मंत्री को बदल कर सरकार भले ही यह संदेश देने का प्रयास करे कि जो मंत्री नतीजे नहीं देगा वो हटा दिया जाएगा लेकिन यह संदेश आम आदमी के दिल तक कितना पहुंचता है यह तो समय ही बताएगा।

यही कारण है कि पांच राज्यों में आगामी चुनावों को देखते हुए तमाम राजनैतिक समीकरणों को साधने का लक्ष्य भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में छुपा है। इसी को देखते हुए देश के इन प्रदेशों के प्रतिनिधियों को शामिल करने से लेकर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को इस मंत्रिमंडल में विशेष रूप से शामिल किया गया। इसके अलावा एनडीए के घटक दलों जैसे जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल को भी इस कैबिनेट विस्तार में शामिल करके भाजपा ने एनडीए

को भी मजबूती प्रदान की है।

लेकिन राजनीति से इतर अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार के सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो यह मंत्रिमंडल शायद आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक का सबसे युवा और पढ़े लिखे नेताओं का मंत्रिमंडल है। योग्यता की बात करें तो इसमें सात पीएचडी, तीन एमबीए, तेरह वकील, छ डॉक्टर, पांच इंजीनियर और सात सिविल सेवक मंत्री हैं।

भारत जैसे देश की राजनीति में निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक स्वागत योग्य बदलाव है। क्योंकि इस देश ने राजनीति में योग्यता के आभाव के बावजूद परिवारवाद अथवा भाई भतीजावाद या फिर वोटबैंक के दम पर अंगूठाछाप से लेकर ऐसे नेताओं को देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे देखा है जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। देश की राजनीति में ऐसे माहौल से जनता त्रस्त थी और राजनेताओं से उनका मोहभंग होने लगा था।

लेकिन इस मंत्रिमंडल में शिक्षित और युवा नेताओं को सरकार में शामिल किया जाना जहां एक ओर आम लोगों के मन में उम्मीद जगाता है तो दूसरी ओर नेताओं को कड़े संदेश भी देता है। इस प्रकार के कदम निश्चित ही देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस कैबिनेट विस्तार के द्वारा प्रधानमंत्री ने दिया है वो यह कि वो महिला सशक्तिकरण की केवल बात ही नहीं करते बल्कि उस दिशा में ठोस कदम भी उठाते हैं।

वित्त, विदेश और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय महिलाओं के हाथ में देकर वो पहले भी महिलाओं में अपना विश्वास व्यक्त कर चुके थे। इस बार उन्होंने सात मंत्रालय महिलाओं के हाथों में सौंपे हैं और अब कुल 11 महिलाएं वर्तमान सरकार में मंत्री है जो महिलाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण का प्रतीक है। तो कहा जा सकता है कि कैबिनेट का यह विस्तार भले ही राजनैतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर या छवि बदलने की कोशिश में किया गया हो लेकिन इसमें राजनैतिक शुचिता और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी विषयों पर जोर देकर वर्तमान राजनीति की दिशा बदलने का एक गंभीर प्रयास भी किया गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। राजनैतिक हितों को साधते हुए इससे बेहतर मंत्रिमंडल विस्तार शायद नहीं हो सकता था।

पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जासूसी के खुलासे से मची खलबली सरकार पर उठे गंभीर सवाल

शिमला। Pegasus Project वैश्विक स्तर पर एक इंवेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में अहम खुलासा हुआ है कि इजराइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर ने भारत के 300 से अधिक मोबाइल फोन नंबर्स को टारगेट किया यानी कि इनकी जासूसी की गई।

एक खुलासे ने दुनियाभर में खलबली मचा दी। पेगासस प्रोजेक्ट (Pegasus software Project) नाम के एक मैलवेयर स्पाइवेयर के जरिए दुनिया भर के उद्योगपतियों, पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के फोन की जासूसी किए जाने की खबर सामने आई।

'द गार्डियन' और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दुनियाभर की कई सरकारों ने 50,000 से अधिक नंबरों को ट्रैक करने के लिए इस पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है। इसमें पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, विपक्षी दलों के नेताओं, जजों आदि को निशाना बनाया गया है।

सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसे किसी भी कारनामें में उनकी संलिप्तता नहीं है।

वाट्सऐप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने कहा है कि 'एनएसओ के ख़तरनाक स्पाइवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में मानवाधिकारों के घोर हनन के लिए किया जाता है और इसे रोका जाना चाहिए।'

द गार्डियन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुनिया भर में 180 पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। भारत में ही 40 से ज़्यादा पत्रकारों के फ़ोन को निशाना बनाया गया। इनके अलावा, रोना विल्सन, डिग्री प्रसाद चौहान, उमर खालिद, जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सोशल एक्टिविस्टों को निशाना बनाया गया है।

'एनडीटीवी' के अनुसार, पेगासस से जिन लोगों की जासूसी की जानी थी, उस सूची में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम भी था। प्रशांत किशोर ने एक के बाद कई चुनावों में विपक्षी दलों के लिए काम किया था, उनके लिए रणनीति बनाई थी, योजना बनाई थी, पार्टी को सलाह दी थी। कुछ दलों को कामयाबी भी मिली।

फ्रांस की ग़ैरसरकारी संस्था 'फ़ोरबिडेन स्टोरीज़' और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने लीक हुए दस्तावेज़ का पता लगाया है और कई समाचार एजेंसियों और संस्थाओं के साथ साझा किया। इसका नाम रखा गया पेगासस प्रोजेक्ट। इज़रायली कंपनी एनएसओ पेगासस सॉफ़्टवेयर बना कर बेचती है। इस सॉफ़्टवेयर के जरिए टेलीफ़ोन के डेटा चुरा लिए गए, उन्हें हैक कर लिया गया या उन्हें टैप किया गया। 'द गार्जियन', 'वाशिंगटन पोस्ट', 'ला मोंद' ने 10 देशों के 1,571 टेलीफ़ोन नंबरों के मालिकों का पता लगाया और उनकी छानबीन की। उसमें से कुछ की फ़ोरेंसिक जाँच करने से यह निष्कर्ष निकला कि उनके साथ पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया था।

पेगासस (Pegasus software Project) एक मैलवेयर है जो आईफोन और एंड्राइड उपकरणों को प्रभावित करता है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को संदेश, फोटो और ईमेल खींचने, कॉल रिकॉर्ड करने और माइक्रोफोन सक्रिय करने की अनुमति देता है।

भारत में भी देश के 40 पत्रकारों की जासूसी पेगासस सॉफ़्टवेयर के ज़रिए की गई है। इसमें 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'द हिन्दू', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'इंडिया टुडे', 'न्यूज़ 18' और 'द वायर' के पत्रकार शामिल हैं। 'द वायर' ने एक ख़बर में यह दावा किया है। 'एनडीटीवी' ने एक ख़बर में कहा है कि इसके अलावा 'संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति' और विपक्ष के तीन नेताओं की जासूसी भी स्पाइवेयर से की गई है।

फ्रांसीसी ग़ैरसरकारी संगठन फ़ोरबिडेन स्टोरीज़ ने जो लीक डाटाबेस हासिल किया है, उसमें गांधी परिवार के इस सदस्य का फ़ोन नंबर भी था। इस सूची में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के पाँच मित्र भी थे, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वे बस राहुल के निजी दोस्त थे। 'द वायर' ने यह दावा किया है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ के ग्राहकों के डाटाबेस में राहुल का नंबर था। लेकिन उस नंबर की फोरेंसिक जाँच नहीं कराई गई है। राहुल गांधी फिलहाल उस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे उसका प्रयोग 2018 – 19 में करते थे। राहुल गांधी के अलावा अलंकार सवाई और सचिन राव के भी नाम संभावित जासूसी की सूची में हैं। सवाई राहुल गांधी के निजी सचिव के रूप में काम करते हैं और उनके तमाम ई – मेल भेजने, फ़ोन करने या रिसीव करने या चिट्टी या मैसेज भेजने का काम वे ही करते हैं। राव कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और उनकी ज़िम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। सवाई के फ़ोन की चोरी 2019 में हो गई और राव का फ़ोन 'फाइड' हो गया, यानी उससे अब फ़ोन नहीं किया जा सकता है।

पेगासस सॉफ़्टवेअर के ज़रिए पत्रकारों, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं और दूसरे लोगों की जासूसी की ख़बर सार्वजनिक होने के बाद एक अहम सवाल यह उठता है कि आखिर यह जासूसी कैसे की गई? मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और 'फोरबिडेन स्टोरीज़' के साथ 80 पत्रकारों ने मिल कर काम किया और हर फ़ोन नंबर के बारे में पता लगाया। उसके बाद सबकी फ़ोरेंसिक जाँच की गई। सरकार या उसकी एजेंसियों की ओर से वैध तरीके से फ़ोन इंटरसेप्ट करने के लिए इंडियन टेलीग्राफ़ एक्ट और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान हैं। लेकिन किसी का फोन हैक करना ग़ैरक़ानूनी है और ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिस तरह पेगासस सॉफ़्टवेअर का इस्तेमाल किया गया पेगासस सॉफ्टवेअर के ज़रिए पत्रकारों, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं और दूसरे लोगों की जासूसी की ख़बर सार्वजनिक होने के बाद एक अहम सवाल यह उठता है कि आख़िर यह जासूसी कैसे की गई? मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और 'फोरबिडेन स्टोरीज़' के साथ 80 पत्रकारों ने मिल कर काम किया और हर फ़ोन नंबर के बारे में पता लगाया। उसके बाद सबकी फ़ोरेंसिक जाँच की गई। सरकार या उसकी एजेंसियों की ओर से वैध तरीके से फ़ोन इंटरसेप्ट करने के लिए इंडियन टेलीग्राफ़ एक्ट और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान हैं। लेकिन किसी का फोन हैक करना ग़ैरक़ानूनी है और ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिस तरह पेगासस सॉफ़्टवेअर का इस्तेमाल किया गया यह हैकिंग है।

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि 189 पत्रकारों, 600 से अधिक राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों और 60 से अधिक व्यावसायिक अधिकारियों को एनएसओ समूह के क्लाइंट द्वारा लक्षित किया गया था, जिसका मुख्यालय इजराइल में है।

फ्रांस की ग़ैरसरकारी संस्था 'फ़ोरबिडेन स्टोरीज़' और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने लीक हुए दस्तावेज़ का पता लगाया और 'द वायर' और 15 दूसरी समाचार संस्थाओं के साथ साझा किया। इसका नाम रखा गया पेगासस प्रोजेक्ट। 'द गार्जियन', 'वाशिंगटन पोस्ट', 'ला मोंद' ने 10 देशों के 1,571 टेलीफ़ोन नंबरों के मालिकों का पता लगाया और उनकी छानबीन की। उसमें से कुछ की फ़ोरेंसिक जाँच करने से यह निष्कर्ष निकला कि उनके साथ पेगासस स्पाइवेअर का इस्तेमाल किया गया था।

फ्रांस की ग़ैरसरकारी संस्था 'फ़ोरबिडेन स्टोरीज़' और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने लीक हुए दस्तावेज़ का पता लगाया और 'द वायर' और 15 दूसरी समाचार संस्थाओं के साथ साझा किया।

इसका नाम रखा गया पेगासस प्रोजेक्ट। 'द गार्जियन', 'वाशिंगटन पोस्ट', 'ला मोंद' ने 10 देशों के 1,571 टेलीफ़ोन नंबरों के मालिकों का पता लगाया और उनकी छानबीन की। उसमें से कुछ की फ़ोरेंसिक जाँच करने से यह निष्कर्ष निकला कि उनके साथ पेगासस स्पाइवेअर का इस्तेमाल किया गया था।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व साइबर सुरक्षा इंजीनियर और अब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में आईटी के निदेशक टिमोथी समर्स ने द वाशिंगटन पोस्ट को बताया, यह गंदा सॉफ्टवेयर है। यह लगभग पूरी दुनिया की आबादी पर जासूसी कर सकता है।

इन पत्रकारों की जासूसी पेगासस के ज़रिए की गई

सिद्धार्थ वरदराजन – द वायर के संस्थापक संपादक
परंजॉय गुहा ठाकुरता – पत्रकार और लेखक
एमके वेणु – द वायर के संस्थापक संपादक
एलिज़ाबेज रोश – मिंट की फोरेन अफ़ेयर्स एडिटर
संदीप उन्नीथन – इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक
औरंगजेब नक्शबंदी – हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संवाददाता
स्वाति चतुर्वेदी – स्वतंत्र पत्रकार
इफ्तिखार गिलानी – कश्मीर के पत्रकार
सुशांत सिंह – इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व एसोसिएट डिप्टी एडिटर
देवीरूपा मित्र – द वायर की पत्रकार
प्रेम शंकर झा – पत्रकार और अर्थशास्त्री
सैकत दत्ता – राष्ट्रीय सुरक्षा कवर करने वाले रिपोर्टर
प्रशांत झा – हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार
स्मिता शर्मा – फोरेन अफ़ेयर्स जर्नलिस्ट, इंडिया अहेड की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर
एसएनएम अब्दी – पत्रकार, लेखक और स्तंभकार
पारुल मलहोत्रा – पूर्व पत्रकार, राजनीति – आर्थिक सलाहकार
जसपाल सिंह हेरन – पत्रकार, पंजाब में पहरेदार के संस्थापक
ऋतिका चोपड़ा – इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ एसिस्टेंट एडिटर
अजित साही – पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मानवाधिकार कार्यकर्ता
मनोरंजन गुप्ता – फ्रंटियर टीवी की प्रधान संपादक
जे गोपीकृष्णन – द पायनियर के विशेष संवाददाता
सिद्धांत सिब्बल – WION के मुख्य रक्षा संवाददाता
संतोष भारतीय, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व सांसद
रोहिणी सिंह – द वायर की पत्रकार
विजेता सिंह, द हिंदू की डेपुटी एडिटर
दीपक गिदवानी – उत्तर प्रदेश के पत्रकार
शाबीर हुसेन बुछ – कश्मीर न्यूज़लाइन के संपादक
मुज़मिल जलील – इंडियन एक्सप्रेस में डेपुटी एडिटर
शिशिर गुप्ता – हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यकारी संपादक
राहुल सिंह – हिंदुस्तान टाइम्स के रक्षा संवाददाता
मनोज गुप्ता – इंडिया टुडे के पत्रकार
भूपिंदर सिंह सज्जन – एएसपी टीवी के संचालक
रुवा शाह – कश्मीर के स्वतंत्र पत्रकार

केंद्र सरकार ने बयान में कहा है कि इससे पहले भी वाट्सऐप के जरिए पेगासस के प्रयोग के आरोप लगाए गए थे लेकिन उस समय भी रिपोर्ट्स में कुछ तथ्य नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में वाट्सऐप समेत सभी पक्षों ने इसका खंडन किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये आरोप भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने वाले प्रतीत होते हैं।

वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर रूख अपनाए हुए है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह गंभीर मामला है और निजता पर हमला है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या भारत अब पुलिस स्टेट में बदल रहा है। इस मसले को मानसून सत्र में उठाए जाने को लेकर विपक्ष अभी विमर्श कर रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा के मुताबिक सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया है कि वे कौन सी एजेंसिया हैं जिन्हें यह मालवेयर मिला और वे कौन सी एजेंसियां है जिन्होंने इसे खरीदा है? सीपीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर बिनॉय विश्वम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने भारत को सर्विलांस स्टेट में बदल दिया है। विश्वम ने संसद में एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए नोटिस देने की बात कही है।

– हिमालय यूके से साभार –

शिमला जिले के कोटखाई और जुब्बल में खुलेंगे एसडीएम कार्यालयः जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 16 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने खड़ापत्थर में जिला स्तरीय स्वर्ण जंयती

ग्राम स्वराज सम्मेलन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दो एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की। इनमें एक एसडीएम कार्यालय जुब्बल जबकि दूसरा कोटखाई में खोला जाएगा। उन्होंने मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब खरीद के मूल्य में एक रूपया प्रति किलो वृद्धि की घोषणा भी की।

जय राम ठाकुर ने कोटखाई में खण्ड विकास कार्यालय, टिक्कर में अग्निशमन उपकेंद्र, कलबोग में उप-तहसील सावड़ा (सरस्वती नगर) और पुलिस स्टेशन सावड़ा को एचपी पावर कॉरपोरेशन के नए भवन में स्थानातंरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में सृजित 9 नई पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 20 लाख प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पंचायतों के विकास के लिए नवीन सुझाव और योजनाएं सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन संस्थानों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है और हमारा प्रदेश व देश भी इससे अछूता नहीं है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी चार हजार करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश कोविड-19 के प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर इत्यादि की कोई कमी नही है। उन्होंने पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के सेब क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार का प्रथम निर्णय गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करने पर केन्द्रित था।

उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न मंडियों में कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी, पर अब राज्य में प्रदेश की भाजपा सरकारों और पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा के द्वारा किए गए प्रयासों से राज्य में कई मंडियां खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि रोहड़ू के मेहंदली और शिमला के भटाकुफर में फल एवं सब्जी मण्डियों के निर्माण के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बागवानों की सुविधा के लिए एमआईएस के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का आग्रह किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं और राज्य सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पराला स्थित फल मंडी का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कोटखाई में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय (बीडीओ) खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या का समुचित रूप से समाधान सुनिश्चित किया है। उन्होंने गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

भाजपा मण्डलाध्यक्ष अनिल कालटा ने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री नरेन्द्र बरागटा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया।

विधायक बलबीर वर्मा, लैंड मॉर्टगेज बैंक की अध्यक्षा शशिबाला, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय श्याम, राज्य भाजपा के आईटी संयोजक चेतन बरागटा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और भाजपा के अन्य प्रमुख नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री द्वारा बीबीएनआईए आगामी पूर्वी औद्योगिक गलियारे के रूप में विचार करने हेतु केन्द्र सरकार का आभार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र (बीबीएनआईए) को आगामी पूर्वी औद्योगिक गलियारे यानी अमृतसर-कोलकात्ता औद्योगिक गलियारे में नोड के रूप में सम्मिलित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आभार व्यक्त किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना लॉजिस्टिक्स की बेहतर सुगमता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को अमृतसर-कोलकात्ता औद्योगिक गलियारे में एक संभावित एकीकृत विन्निर्माण कलस्टर के रूप में जोड़ने के प्रस्ताव पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के शिमला दौरे के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत किया था और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस निर्णय से उत्पादन के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को सुविधा प्राप्त होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक पार्क जैसे चिकित्सा उपकरण पार्क, ऊर्जा उपकरण हब, इलैक्ट्रॉनिक उत्पादन कलस्टर, प्लास्टिक पार्क और विद्युत उपकरण हब के विकास के लिए उद्योग विभाग को 2500 हेक्टेयर लैंड बैंक आवंटित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के निवेश से डिफेंस पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से राज्य कॉरीडोर में और इसके आस-पास औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश को अत्याधुनिक औद्योगिक प्वाइंटशिप स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

भारत सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटीज् के रूप में विकसित करना है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट देश में सभी पांच औद्योगिक कॉरीडोर के विकास के लिए समन्वित और एकीकृत विकास के लिए प्रमुख संस्था है।

प्रदेश में वर्ष 2021–22 में रोपे जाएंगे एक करोड़ पौधे

शिमला/शैल। वनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने और पौधरोपण में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेश में हर वर्ष वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई, 2021 को कुल्लू जिला के निरमंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे।

वन विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। विभाग द्वारा नगर परिषदों और पंचायतों के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय लोगों की सहायता से पौधरोपण के लिए 51 पौधे प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष 20 एवं 21 जुलाई को दो दिवसीय बृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं द्वारा 10 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से एक लाख पौधे भी रोपित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जंयती वर्ष के अवसर पर वन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 34 स्वर्णिम वाटिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। इस वर्ष 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को लैंटाना से मुक्त कर वहां पौधरोपण की योजना भी तैयार की गई है।

उन्होंने बताया कि जुलाई 2018 से वन महोत्सव के दौरान वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्थानीय समुदायों के सहयोग से विशेष पौधरोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में तीन दिनों तक आयोजित अभियान के दौरान प्रदेश में लगभग 600 स्थानों पर सरकारी विभागों, स्थानीय समुदायों, आम लोगों, महिला मंडलों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों के विद्यार्थियों की मदद से लगभग 26 लाख 50 हजार पौधे रोपित किए गए। वर्ष 2019 में वन महोत्सव के दौरान आयोजित 5 दिवसीय अभियान के दौरान 1 लाख 35 हजार लोगों की सहभागिता से 31 लाख 60 हजार पौधे रोपित किए गए।

उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण में वनों का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है। राज्य के 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 4.96 प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्र, 33.87 प्रतिशत सीमांकित वन, 42.25 प्रतिशत गैर सीमांकित संरक्षित वन और 18.87 प्रतिशत अन्य वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 27.72 प्रतिशत हरित आवरण है। वन विभाग ने वर्ष 2030 तक हरित आवरण को 30 प्रतिशत और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग द्वारा अनेक पहल की गई हैं। पौधरोपण बढ़ाने और वनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से एक बूटा बेटी के नाम, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना सहित अनेक महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

एसबीआई एमएसएमई क्षेत्र के विकास में हमेशा सबसे आगे रहा हैः प्रबंध निदेशक

शिमला/शैल। भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमई क्षेत्र के विकास में हमेशा सबसे आगे रहा है। 15 जुलाई, 2021 को शिमला में एसबीआई एओ शिमला द्वारा एक एमएसएमई ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक (खुदरा और डिजिटल बैंकिंग) सीएस शेट्टी ने की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों ने भाग लिया। ग्राहकों को संबोधित करते हुए, सीएस शेट्टी ने सुझाव दिया कि मध्यम उद्यमों से बड़े कारपोरेट तक बढ़ने के लिए प्रमोटरों को मुख्य रूप से तीन बिदुओं यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने ग्राहकों को योनो व्यवसाय और भारत क्राफ्ट सहित बेहतर एसएमई ग्राहक वितरण के लिए बैंक द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बताया।

बैठक के दौरान ग्राहकों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया गया और उनके सुझाव भी लिए गए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मुख्य महाप्रबंधक, चंडीगढ़ सर्कल अनुकुल भटनागर, सीजीएम डेजिगनेट नेटवर्क चंडीगढ़ सर्कल बिनोद कुमार मिश्रा और डिप्टी जनरल मैनेजर, एओ शिमला वपन कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

भाजपा के लिये आसान नही होगा उपचुनावों के लिये उम्मीदवारों का चयन करना गोविन्द के तेवरों से उठी चर्चा

शिमला/शैल। प्रदेश में चार उपचुनाव होने जा रहे हैं जिनमें तीन विधानसभा के लिये और एक लोकसभा के लिये। विधानसभा के तीन रिक्त स्थानों में 2017 में दो कांग्रेस के पास और एक भाजपा के पास रहा है। लोकसभा की चारों सीटें 2014 में भी और 2019 में भी भाजपा के पास ही रही है। बल्कि जीत का अन्तर 2019 में 2014 के मुकाबले कही ज्यादा रहा है। 2014 के बाद हुए सभी चुनाव कांग्रेस हार गयी है। केवल इस बार चार नगर निगमों के लिये हुए चुनावों में कांग्रेस सोलन और पालमपुर की नगर निगम में जीत कर इस पर ब्रेक लगाने में सफल हुई है। इस वस्तुस्थिति में आज दोनों पार्टीयां कांग्रेस और भाजपा की साख दांव पर लगी हुई है। भाजपा और जयराम सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह चारों सीटों पर जीत दर्ज करे। यदि जयराम के नेतृत्व में भाजपा ऐसा कर पाती है तभी जयराम का कब्जा नेतृत्व पर बना रहेगा। अन्यथा उस पर सवाल लगने शुरू हो जायेंगे। इन उपचुनावों में शायद प्रधानमन्त्री और गृह मन्त्री अमितशाह चुनाव प्रचार के लिये न आ पायें। इसलिये यह उपचुनाव पूरी तरह प्रदेश नेतृत्व की ही परीक्षा माने जायेंगे।

इन चुनावों में टिकटों का बंटवारा भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि चारों स्थानों के लिये कई कई प्रत्याक्षी दावेदारी जताने पर आ गये हैं। विधानसभा के लिये फतेहपुर जुब्बल कोटखाई और अर्की तीनों ही स्थानों पर पार्टी में बगावत के स्वर सामने आने लग पड़े है। फतेहपुर में राजन सुशांत लम्बे अरसे से ओल्ड पैन्शन स्कीम के मुद्दे पर कर्मचारीयों का समर्थन जुटाने के लिये धरने पर हैं। राजन सुशांत को मनाने के लिये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत पाल सत्ती का उनसे मिलना चर्चा में आ चुका है और इसी से वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में और रोष पनप गया है। अर्की में 2017 में वहां से दो बार विधायक रह चुके गोविन्द राम शर्मा का टिकट काट कर रतन पाल को उम्मीदवार बनाया गया था। वह वीरभद्र सिंह से चुनाव हार गये थे। लेकिन हारने के बाद भी उनकी सरकार और संगठन में ताजपोशी कर दी गयी। जबकि गोविन्द राम शर्मा के साथ उस समय किये गये वायदे आज तक वफा नही हुये हैं। इस बेवफाई पर गोविन्द और उनके समर्थकों का नाराज होना स्वभाविक है। अब जब अर्की में उपचुनाव आ खड़ा हुआ है तब गोविन्द और उनके समर्थकों को अपनी नाराज़गी जाहिर करने का मौका मिल गया। दाड़लाघाट में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक करके गोविन्द ने इस नाराज़गी को उजागर भी कर दिया है। इस नाराजगी के बाहर आते ही प्रभारी को अर्की पहुंचना पड़ा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार गोविन्द राम शर्मा से किये गये वायदे कितने सिरे चढ़ते हैं।

जुब्बल कोटखाई में जो दरार एक समय स्व.बरागटा और शहरी विकास मन्त्री सुरेश भारद्वाज के बीच रही है वह शायद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सुरेश भारद्वाज को जब इस उप चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तब यह पुराने प्रंसग एक बार फिर सामने आ चुके हैं। इसी स्थिति को जानकर आज मुख्यमन्त्री को यहां पर चुनावों से पहले दो एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा करनी पड़ी है। चुनावों के लिये किये गये वायदे कितने पूरे होते हैं यह सभी जानते हैं। इसी तरह मण्डी लोकसभा के लिये तो स्थिति और भी रोचक होगी। इस चुनाव की जिम्मेदारी संभाले जल शक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह के ब्यानों से पैदा हुए विवादों को राजनीतिक विश्लेषक एक सोची समझी चाल मान रहे हैं। फिर यहां पर स्व. रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के बाद राम स्वरूप शर्मा के बेटे ने भी इसे आत्महत्या का मामला मानने की बजाये इस हत्या का मामला मानकर जांच करने की मांग कर दी है। वह इस संद्धर्भ में केन्द्रिय मन्त्री नितिन गडकरी से भी इस आश्य की गुहार लगा चुका हैं। रामस्वरूप के बेटे के इस ब्यान का कोई खण्डन नही कर पाया है। यह सवाल इस चुनाव में अहम मुद्दा बन सकता है। इस परिदृश्य में मण्डी लोकसभा के लिये उम्मीदवार का चयन करना आसान नही होगा।

एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को तीन वर्षों से नहीं मिली छात्रवृति

शिमला/शैल। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों तथा गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये करीब 34 छात्रवृति योजनाएं शुरू कर रखी हैं। यह योजनाएं सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे इन वर्गो के छात्रों पर बराबर लागू होती हैं। इस छात्रवृति योजना में एक समय करीब 250 करोड़ का घपला होने के आरोप लगे थे। इन आरोपों पर शिक्षा विभाग ने राज्य परियोजना अधिकारी शक्ति भूषण से प्रारिम्भक जांच करवाई थी और उसकी रिपोर्ट पर 16 – 11 – 2018 को पुलिस थाना छोटा शिमला में एफआईआर दर्ज करवायी थी। आगे चलकर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। यह जांच शैक्षणिक सत्र 2016 – 17 तक सीमित थी। इसमें सीबीआई ने 266 संस्थानों का रिकार्ड कब्जे में लिया है। शिक्षा विभाग और कुछ प्राईवेट संस्थानों के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस जांच पर अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं आया है।

इन योजनाओं के तहत यह बच्चे प्रदेश से बाहर स्थित संस्थानों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री करने के लिये इन छात्रों को प्रतिवर्ष करीब 3,80,000 रूपये दिये जाते हैं। स्वभाविक है कि इन वर्गो के छात्र इतना खर्च अपनी जेब से नही कर सकते और सरकार द्वारा छात्रवृति भुगतान पर ही इनकी पढ़ाई निर्भर करती है। पंजाब के मोहाली स्थित विद्या ज्योति संस्थान की हिमाचल स्टूडैण्ट वैल्फेयर ऐसोसियेशन के प्रैस नोट से यह सामने आया है कि इन वर्गो के छात्रों को वर्ष 2017 – 18 और 2019 की छात्रवृति का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। यह छात्र कई बार सरकार के सामने अपनी समस्या रख चुके हैं। सीबीआई केस के नाम पर इनकी छात्रवृति रोकी गयी है जबकि इनका दाखिला ही 2016 के बाद का है।

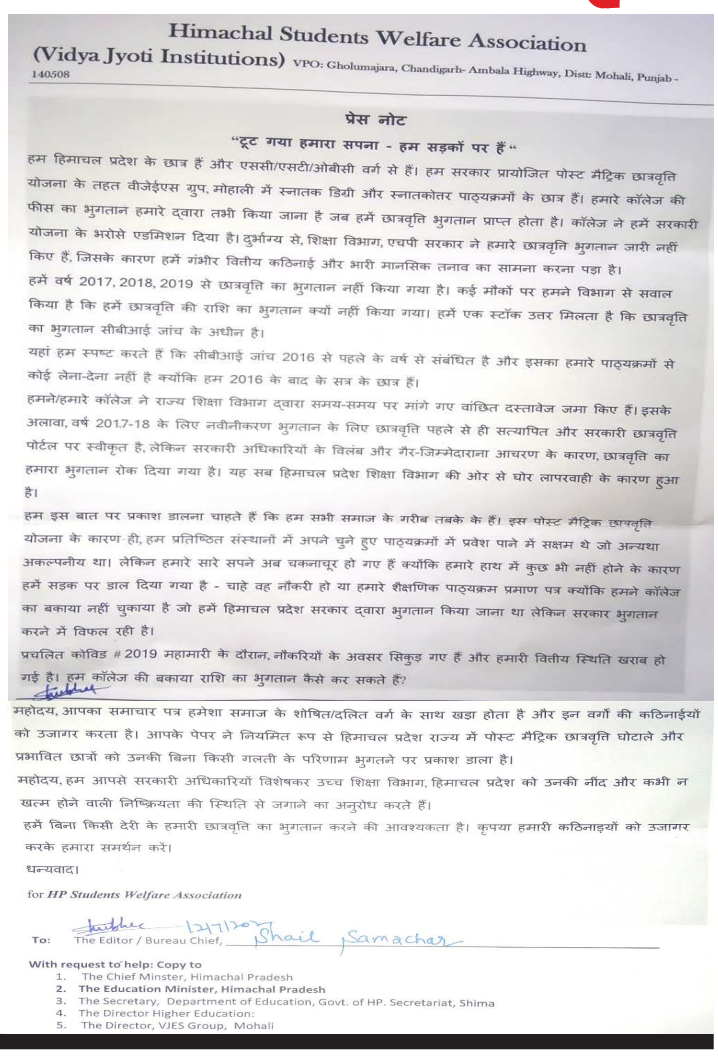

Himachal Students Welfare Association
(Vidya Jyoti Institutions) VPO: Gholumajara, Chandigarh- Ambala Highway, Distt: Mohali, Punjab - 140508

प्रेस नोट

"टूट गया हमारा सपना - हम सड़कों पर हैं"

हम हिमाचल प्रदेश के छात्र हैं और एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग से हैं। हम सरकार प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वीजेईएस ग्रुप, मोहाली में स्नातक डिग्री और स्नातकोतर पाठ्यक्रमों के छात्र हैं। हमारे कॉलेज की फीस का भुगतान हमारे द्वारा तभी किया जाना है जब हमें छात्रवृति भुगतान प्राप्त होता है। कॉलेज ने हमें सरकारी योजना के भरोसे एडमिशन दिया है। दुर्भाग्य से, शिक्षा विभाग, एचपी सरकार ने हमारे छात्रवृति भुगतान जारी नहीं किए हैं, जिसके कारण हमें गंभीर वित्तीय कठिनाई और भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है।

हमें वर्ष 2017, 2018, 2019 से छात्रवृति का भुगतान नहीं किया गया है। कई मौकों पर हमने विभाग से सवाल किया है कि हमें छात्रवृति की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। हमें एक स्टॉक उत्तर मिलता है कि छात्रवृति का भुगतान सीबीआई जांच के अधीन है।

यहां हम स्पष्ट करते हैं कि सीबीआई जांच 2016 से पहले के वर्ष से संबंधित है और इसका हमारे पाठ्यक्रमों से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि हम 2016 के बाद के सत्र के छात्र हैं।

हमने/हमारे कॉलेज ने राज्य शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर मांगे गए वांछित दस्तावेज जमा किए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के लिए नवीनीकरण भुगतान के लिए छात्रवृति पहले से ही सत्यापित और सरकारी छात्रवृति पोर्टल पर स्वीकृत है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के विलंब और गैर-जिम्मेदाराना आचरण के कारण, छात्रवृति का हमारा भुगतान रोक दिया गया है। यह सब हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से घोर लापरवाही के कारण हुआ है।

हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि हम सभी समाज के गरीब तबके के हैं। इस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के कारण ही, हम प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने चुने हुए पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में सक्षम थे जो अन्यथा अकल्पनीय था। लेकिन हमारे सारे सपने अब चकनाचूर हो गए हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होने के कारण हमें सड़क पर डाल दिया गया है - चाहे वह नौकरी हो या हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र क्योंकि हमने कॉलेज का बकाया नहीं चुकाया है जो हमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाना था लेकिन सरकार भुगतान करने में विफल रही है।

प्रचलित कोविड # 2019 महामारी के दौरान, नौकरियों के अवसर सिकुड़ गए हैं और हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। हम कॉलेज की बकाया राशि का भुगतान कैसे कर सकते हैं?

महोदय, आपका समाचार पत्र हमेशा समाज के शोषित/दलित वर्ग के साथ खड़ा होता है और इन वर्गों की कठिनाईयों को उजागर करता है। आपके पेपर ने नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति घोटाले और प्रभावित छात्रों को उनकी बिना किसी गलती के परिणाम भुगतने पर प्रकाश डाला है।

महोदय, हम आपसे सरकारी अधिकारियों विशेषकर उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को उनकी नींद और कभी न खत्म होने वाली निष्क्रियता की स्थिति से जगाने का अनुरोध करते हैं।

हमें बिना किसी देरी के हमारी छात्रवृति का भुगतान करने की आवश्यकता है। कृपया हमारी कठिनाइयों को उजागर करके हमारा समर्थन करें।

धन्यवाद।

for HP Students Welfare Association

To: The Editor / Bureau Chief, Shail Samachar

With request to help: Copy to
1. The Chief Minster, Himachal Pradesh
2. The Education Minister, Himachal Pradesh
3. The Secretary, Department of Education, Govt. of HP. Secretariat, Shima
4. The Director Higher Education:
5. The Director, VJES Group, Mohali